रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072023-247666
CG-DL-E-27072023-247666

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 440] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 27, 2023/श्रावण 5, 1945
No. 440] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 27, 2023/SHRAVANA 5, 1945

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 560(अ).—केंद्रीय सरकार भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र अधिनियम, 2019 (2019 का 17) की धारा 30 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय, वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात:—

1. (1). इन नियमों को भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय, वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें) दूसरा संशोधन नियम, 2023 कहा जाए।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारत अंतर्राष्ट्रीय माध्यस्थम केंद्र (अध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों को संदेय, वेतन और भत्ते तथा निबंधन और शर्तें) नियम, 2022 के नियम 7 में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"बशर्ते कि अध्यक्ष के रूप में किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति के मामले में, जो भारत के उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, अध्यक्ष अपने संबंधित मूल वेतन के सत्ताईस प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता या मुक्त सुसज्जित आवास का हकदार होगा।

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजन के लिए, किराया मुक्त सुसज्जित आवास में शामिल है,-

(क) आधिकारिक सुसज्जित निवास, कर्मचारी आवास और अन्य भवन, अपार्टमेंट और उसका बगीचा और उक्त निवास के संबंध में रखरखाव शुल्क, जिसमें स्थानीय दरों और करों व बिजली और पानी का भुगतान शामिल है;

(ख) अध्यक्ष, जो भारत के उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीश रहे हों, के मामले में आधिकारिक आवास में अधिकतम क्रमशः 10,00,000 रुपये और 8,00,000 रुपये की निःशुल्क साज-सज्जा (विद्युत उपकरणों सहित) प्रदान की जाती है, और अध्यक्ष , जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहे हो, के मामले में अधिकतम क्रमशः 8,00,000/- and Rs. 6,00,000/- रुपये की राशि होगी।"

[फा. सं. ए 60011/48/2022-एनडीआईएसी (एलए)]

डॉ राजीव मणि, अपर सचिव

नोट : भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में जी.एस.आर. 442(ई), दिनांक 11 जून, 2022 के द्वारा मूल नियम प्रकाशित किए गए थे और मूल नियमों को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i), दिनांक 13 फरवरी, 2023, जी.एस.आर. 109 (ई) के द्वारा संशोधित किया गया।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2023

G.S.R. 560(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (a) of sub-section (2) of section 30 of the India International Arbitration Centre Act, 2019 (17 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the India International Arbitration Centre (Terms and Conditions and the Salary and allowances payable to Chairperson and Full-time Members) Rules, 2022, namely:—

1. (1) These rules may be called the India International Arbitration Centre (Terms and Conditions and the Salary and allowances payable to Chairperson and Full-time Members) Second Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 7 of the India International Arbitration Centre (Terms and Conditions and the Salary and allowances payable to Chairperson and Full-time Members) Rules, 2022, the following proviso shall be inserted, namely:-

"Provided that in case of appointment of a person as Chairperson, who has been a judge of the Supreme Court of India or High Court, the Chairperson shall be entitled to a rent free furnished accommodation or house rent allowance at the rate of twenty-seven percent of their respective basic pay.

***Explanation*.-** For the purpose of this rule, rent free furnished accommodation includes,-

(a) official furnished residence, the staff quarters and other buildings apartment thereto and the garden thereof and maintenance charges in relation to the said residence, including the payment of local rates and taxes and electricity and water;

(b) free furnishing (including electrical appliances) provided free of rent in the official residence in case of Chairperson who has been the Chief Justice of India or a Judge of Supreme Court, the value of which shall not exceed Rs.10,00,000 and Rs.8,00,000 respectively and in case of Chairperson who has been the Chief Justice of a High Court or a Judge of a High Court, the value of which shall not exceed Rs. 8,00,000/- and Rs. 6,00,000/- respectively."

[F. No. A 60011/48/2022-NDIAC (LA)]

Dr. RAJIV MANI, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published *vide* G.S.R. 442(E), dated the 11th June, 2022, in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 11th June, 2022 and the principal rules were amended *vide* G.S.R. 109 (E), dated the 13th February, 2023 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated the 13th February, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA